



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 940]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2005/भाद्र 16, 1927

No. 940]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2005/BHADRA 16, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2005

का.आ. 1243(अ).—अतः माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 2004 की 2947, फारवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया, बनाम संघ सरकार एवं अन्य में 5 मई, 2005 को यह निर्देश दिया है कि वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 150 के तहत एक अधिकरण गठित किया जाए तथा याचिकाकर्ता द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए गए विवाद को उस अधिकरण को सौंपा जाए।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत सरकार के राजपत्र असाधारण में का.आ. 1113(अ) दिनांक 10 अगस्त, 2005 के द्वारा एक अधिकरण का गठन किया गया था और श्री आर. आर. सिन्हा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (महाराष्ट्र, 1976), प्रधान सचिव (परिवहन एवं राज्य उत्पाद) को उक्त अधिकरण में नियुक्त किया गया था। अब श्री आर. आर. सिन्हा, ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2005 से सरकारी सेवा से स्वैच्छा से अवकाश ग्रहण करने के लिए प्रार्थना की है और इसलिए वह अधिकरण के कार्य को नहीं निभा पाएंगे।

अतः, इस मंत्रालय की अधिसूचना जो भारत सरकार के राजपत्र असाधारण में का.आ. 1113(अ) दिनांक 10 अगस्त, 2005 को प्रकाशित हुई थी, का अतिक्रमण करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा एक अधिकरण का गठन करती है, जिसका मुख्यालय मुम्बई में होगा और याचिकाकर्ता द्वारा उठाये गये विवाद को सौंपती है और श्रीमती प्रतिमा उमरजी, प्रधान सचिव (सेवानिवृत्त) महाराष्ट्र सरकार, को उक्त अधिकरण में नियुक्त करती है, जो सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 4 माह के भीतर केन्द्र सरकार को अधिकरण का अधिनिर्णय प्रस्तुत करेगा। उक्त अधिकरण को सौंपे गए विचारार्थ विषय और शर्तें अधोलिखित अनुसूची में दी गई हैं।

अनुसूची

(क) विचारार्थ विषय

फारवर्ड सीमैन यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 2004 की 2947 में उठाये गये मुद्दों की जांच करना तथा बम्बई उच्च न्यायालय के उपरोक्त रिट याचिका में 5 मई, 2005 के आदेश में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करना तथा उचित अनुशसाएं देना।

(ख) शर्तें

- (i) अधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में होगा और इसे सचिवालय सहायता, नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- (ii) अधिकरण द्वारा कार्यवाही करने पर तथा टी. ए./ डी. ए. के रूप में होने वाला व्यय तथा अन्य सम्बद्ध व्यय नौवहन महानिदेशालय, मुम्बई द्वारा यात्रा व्यय और कार्यालय व्यय शीर्ष से वहन किया जाएगा।
- (iii) अधिकरण, किसी व्यक्ति अथवा नाविकों के किसी संघ, मामले से संबंधित व्यक्तियों और जहाज के मालिकों को साक्ष्य देने और विचारार्थ विषय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से बुला सकता है। अधिकरण, यदि चाहे तो उन पदाधिकारियों को भी, जो नेशनल मैरीटाइम बोर्ड के समझौते तय कराने में शामिल होते हैं, स्पष्टीकरण, रिकार्ड्स की प्रस्तुति हेतु अथवा किसी अन्य वांछित सूचना हेतु, अधिकरण की कार्यवाही के दौरान बुला सकता है।
- (iv) एक सदस्यीय अधिकरण की अध्यक्ष को प्रति बैठक (प्रतिदिन) 1500 रुपए भत्ता दिया जाएगा और वह नियमों के तहत देय टी. ए./डी. ए. के लिए भी प्राप्त होंगे। (व्याख्या—एक बैठक—प्रत्येक बार एक बैठक पांच घंटे से कम नहीं होगी)।
- (v) अधिकरण की कार्यवाही माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने निश्चित की है जिसमें यह कहा गया है कि अधिकरण अपना अधिनिर्णय गठन के 4 माह के अन्दर प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. एस. आर.-11014/2/2005-एम.ए.]

डी. टी. जोसेफ, सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2005

S.O. 1243(E).— Whereas the Hon'ble High Court of Bombay vide order dated 5-5-2005 in Writ Petition No. 2947 of 2004, Forward Seamen's Union of India Versus Union of India & others has directed that a Tribunal may be constituted under Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958) and refer the dispute raised by the petitioner in this regard.

Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 150 of the Merchant Shipping Act, 1958 One Person Tribunal was constituted and Shri R. R. Sinha, IAS (MH, 1976), Principal Secretary (Transport & State Excise), Home Department, Mantralaya, Mumbai was appointed to the said Tribunal vide this Ministry's notification of even number published in the Gazette of India Extraordinary under No. S.O. 1113(E) dated 10th August, 2005. Now Shri R.R. Sinha has sought voluntary retirement from the Government Service w.e.f. 15th October, 2005 and therefore, he shall not be able to discharge the duties of One Person Tribunal.

Now, Therefore, in supersession of this Ministry's notification of even number published in the Gazette of India Extraordinary under No. S.O. 1113(E) dated 10th August, 2005 and in exercise of the powers conferred by Section 150 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal, with headquarters at Mumbai and refers the dispute raised by petitioner and appoints Smt. Pratima Umerji, Principal Secretary (Retired), Government of Maharashtra, to the said Tribunal who shall submit the award of the Tribunal to the Central Government within 4 months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette. The Terms of Reference and the Terms & Conditions of said Tribunal are set out in the Schedule given below.

SCHEDULE

(A) TERMS OF REFERENCE

To examine the issues raised by the petitioner in the Writ Petition No. 2947 of 2004 filed by the Forward Seamen's Union of India and to follow the directions of the Hon'ble High Court of Bombay in the order dated 5-5-2005 in the above mentioned Writ Petition and to make appropriate recommendations.

(B) TERMS AND CONDITIONS

- (i) The Tribunal shall have its headquarters at Mumbai and Secretarial Assistance shall be provided by the Office of the Directorate General of Shipping, Mumbai.

- (ii) The expenditure incurred by the Tribunal in conducting the proceedings and TA/DA and Other allied expenses shall be met out of travel and Office Expenses Budget of the Directorate General of Shipping, Mumbai.
- (iii) The Tribunal may invite individuals or any union of seamen, persons connected with the matter and owners of ships for giving evidence and for obtaining information relevant to the Terms of Reference. Tribunal may also invite such other office bearers who are involved in concluding the NMB Agreements for any clarification and production of records, information as required, during the proceedings of the Tribunal.
- (iv) The Chairperson of the One Person Tribunal shall be paid Rs. 1500/ per sitting (or per day) and would also be entitled to TA/DA, as admissible under the rules, (Explanation: One sitting shall not be less than five hours on each occasion).
- (v) The term of the Tribunal has been decided by the Hon'ble High Court of Bombay wherein it has been stated that the Tribunal shall submit its award within 4 months after it is constituted.

[F.No. SR-11014/2/2005-MA]

D. T. JOSEPH, Secy.